(b) and (c) Do not arise.

. Encroachment on road in Shalimar Bagh

3267. SHRI SUKOMAL SEN : Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a road of 100 feet wide between block 'B' pocket H East to Block 'B' Pocket J (East) Shalimar Bagh was constructed - for the convenience of redidents living in the houses built on 70 sq. metres plots;

(b) whether it is also a fact that jhuggi jhopri dwellers have encroached upon this road constructing jhuggies thereon resulting into the closure of this road; and

(c) if so, what remedial steps Government propose to take to vacate this encroachment ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH): (a) There is 18 meter wide and 100 feet wide road between Pocket H to J in Block B.

(b) No, Sir. The J.J. clusters are on the area where the land use was Group Housing Society & District **Park.**

(c) Does not arise in view of reply to part (b) above.

बिना बारी फ्लैटों के आवंटन के लिए लम्बित आवेदन

3268. **श्री विश्वासराव रामाराव पाटिल :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों के बिना बारी आवंटन के लिए सरकार के पास आवेदन लम्बित पड़े हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है, विधवाओं, विकलांगों और अन्य व्यक्तियों की श्रेणियों के कितने व्यक्तियों ने अलग-अलग अनुकम्पा के आधार पर फ्लैटों के आवंटन के लिए आवेदन किया है ; और

(ग) इन आवेदनों के कब तक निपटा दिये जाने की संभावना है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) स्व-वित्त पोषित योजना फ्लैटों के लिए 45 तथा मध्यम आय वर्ग, निम्न आय वर्ग और जनता फ्लैटों के लिए 265 आवेदन पत्र बिना बारी का आवंटनार्थ लम्बित हैं । स्व-वित्त पोषित योजना फ्लैटों के लिए आवेदनों के ब्यौरे अनुलग्नक- 1 में तथा अन्य फ्लैटों के लिए आवेदनों के ब्यौरे अनुलग्नक II में दिये गये हैं । [देखिए परिशिष्ट CLI, अनुपत्र सं० 183] ।

(ग) सामान्यत: आवेदन पत्रों पर कार्यवाही की जाती है, और आवेदन पत्रों के साथ सभी अपेक्षित दस्तावेज होने और आवेदन पत्र पूर्ण होने की स्थिति में 45 दिन के अन्दर-अन्दर निर्णय लिया जाता है ।

संसद सदस्यों को फ्लैटों का आवंटन

3269. **श्री विश्वासराव रामाराव पाटिल:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा संसद सदस्यों को फ्लैट आवंटित किये गये हैं ;

(ख) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उसका मानदण्ड क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

3270. [*Withdrawn*]

दूध की घटिया थैलियों की सप्लाई

3271. **डा० रत्नाकर पाण्डेय** : कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा सप्लाई की गयी दूध की थैलियां घटिया दर्जे की होती हैं जो सामान्यतया रिसती रहती हैं ;

(ख) यदि हां, तो दूध की थैलियों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सरकार क्या प्रभावी कदम उठा रही है ;

(ग) दूध की थैलियों का प्रयोग करने से पहले उनकी क्वालिटी की जांच करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(घ) क्या सरकार दूध की थैलियों पर पैकिंग की तिथि निर्दिष्ट करने का विचार रखती है; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) से (ग) दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा वितरित की जा रही दूध की थैलियां घटिया दर्जे की नहीं हैं । थैलियां बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री (फिल्म) की क्वालिटी का, वितरण पद्धति में उपयोग किये जाने से पहले मजबूती; सघनता और अन्य संगत मानदण्डों की दृष्टि से पर्याप्त रूप से परीक्षण किया जाता है ।

(घ) इसकी जांच कर ली गयी है और इसे उपलब्ध औद्योगिकी जो हमारी आवश्यकताओं के अनुकूल है की दृष्टि से अव्यवहार्य पाया गया है ।

Cases pending under Industrial Disputes Act, 1947

3272. SHRI SHIV PRATAP MISHRA: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) what is the number of cases under Industrial Disputes Act, 1947 pending with the Industrial Tribunals as on the 31st July, 1989; and

(b) what steps are being taken for clearing the backlog ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RADHAKISHAN MALAVIYA: (a) and (b) The information is bing collected and will be placed on the Table of the House.

Number of vacancies in the Industrial Tribunals and Labour Courts

3273. SHRI SHIV PRATAP MISHRA: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) what is the number of Industrial tribunals and labour courts in the country where the posts of Judges are lying vacant as on the 31st July, 1989; the time since when these vacancies are lying vacant; and

(b) the steps taken to fill the vacancies ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR AND THE MINISTER OF STATE THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RADHAKISHAN MALAVIYA): (a) The The Central Government has set up 11 Central Government Industrial Tribunals-cum-Labour Courts in the country. As on 31st July, 1989, two